Judge-population ratio in the country

1283. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that judge-population ratio in the country is the lowest i.e. only two judges for every 15 lakhs of population;

(b) whether it is also a fact that Law Commission had suggested an increase in the number of judges; and

(c) if so, the steps taken/porposed to be taken to improve the ratio ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) to (c) The Law Commission in its 120th Report had, among others, recommended that the present strength of 10.5 Judges per million population be increased to 50 Judges per million population. The report has been circulated to all the State Governments/UT Administration. So far as the recommendations relating to High Courts are concerned, it has been decided not to accept the proposal to increase Judge-strength only on the basis of population.

Pending cases before the Lucknow Bench of the Allahabad High Court

1284. SHRI SHANTI TYAGI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the total number of cases of all types and categories pending before the Lucknow bench of the Allahabad High Court;

(b) the estimated number of cases disposed of by this bench yearly; and

(c) what proposals Government have considered to get this arrears of cases disposed of at the earliest ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The various recommendations made by the Arrears Committee, which examined the problem of arrears in the Courts, covering various aspects have been commended to all concerned State Governments/High Courts including the Allahabad High Court for necessary follow-up action. As per the decision taken in the Law Ministers Conference held in October, 1992 at Bangalore, three working groups of the State Law Ministers have been constituted to suggest measures for the implementation of the recommendations of the Arrears Committee so as to expedite the disposal of pending cases in the Courts.

Election to the National Capital Assembly (Delhi)

1285. CHOWDHRY HARI SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there was a demand put forth by the political parties recently to hold election in Delhi;

(b) by when election in Delhi are likely to be held; and

(c) the reasons for the delay in holding the elections in Delhi ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) The Government has not recently received any representation from any political party to hold elections in Delhi;

(b) and (c) The work relating to preparation of electoral rolls has not yet been completed. It is therefore not possible, at present, to indicate the likely dates of elections in Delhi.

गुजरात के न्यायालयों में दुर्घटना दावा संबंधी मामले

1286. श्री राम सिंह राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिला न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में कितने दुर्घटना दावा संबंधी मामले निपटानार्थ विचाराधीन हैं; और

(ख) इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) तारीख 31-10-1992 को गुजरात उच्च न्यायालय में दुर्घटना दावा के 3608 मामले लंबित थे । जिला न्यायालयों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बकाया मामला समिति, जिसने न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या की समीक्षा की थी, द्वारा की गई सिफारिशें, जिनमें न्यायपालिका में अधिकारिता विषयक और प्रक्रियात्मक उपान्तरण सुधार; न्यायालयों में कार्यालय उपस्करों के आधुनिकीकरण सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं और न्यायालयों में दिन-प्रतिदिन के कार्य में सुधार; सुलह न्यायालयों की स्थापना और इसे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों आदि के समक्ष कार्यवाहियों को भी लागू करना, जैसे विभिन्न पहलू सम्मिलित हैं, गुजरात उच्च न्यायालय सहित सभी संबद्ध राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं ।

लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्य-विधानमंडलों के चुनाव

1287. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्य-विधान मंडलों में कुल कितने स्थान रिक्त हैं और इन स्थानों के लिए कब तक चुनाव कराए जाने की संभावना है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : रिक्त स्थानों की बाबत जानकारी निम्नलिखित है :—

लोक सभा—बारह

राज्य सभा—नौ

राज्य विधान सभाएं—पैंतीस

राज्य विधान परिषदें—सैंतालीस

निर्वाचन आयोग लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के सभी उन रिक्त स्थानों पर, जहां न्यायालय का व्यादेश नहीं है, अप्रैल और मई, 1993 में निर्वाचन कराने के लिए पहले ही कदम उठा चुका है । जम्मू-कश्मीर में लोक सभा के छह स्थानों पर, विधि और व्यवस्था की स्थिति अनुकूल होते ही, निर्वाचन करा लिए जाएंगे । जहां तक राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों में रिक्त स्थानों का संबंध है तीन रिक्त स्थानों को छोड़कर, अन्य सभी की बाबत निर्वाचकगण विद्यमान नहीं है । दो रिक्त स्थानों के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और तीसरे स्थान से संबंधित मामला न्यायाधीन है ।

Legal provisions to discourage non-serious contestants in general elections

1288. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether large number of contestants in a constituency poses difficulties in conducting elections; and

(b) if so, what action is proposed to be taken by Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) Yes, Sir.

(b) Certain provisions such as increasing the security deposit, increase in the number of proposers etc. are under consideration of the Government to discourage non-serious candidates from contesting elections.

मतदाताओं को पहचान पत्र दिया जाना

1289. **श्री सोमपाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) इस कार्य पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय होगी ?